5.00 P.M.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

Points arising out of the Answer to starred Question No. 522 given in the Rajya Sabha on the 2nd may 2005 Regarding 'Extension of MID Day Meal Scheme'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Jesudasu to raise a discussion on points arising out of the answer given in Rajya Sabha on the 2nd May, 2005 to Starred Question No. 522 regarding 'Extension of Mid Day Meal Scheme'.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I rise to initiate the discussion on the points raised in reply to Starred Question No. 522, taken up on the 2nd May 2005 regarding 'Extension of Mid Day Meal Scheme up to High School Level'. Sir, while answering, the hon. Minister was kind enough to clarify so many issues. Sir, the main thrust was on a particular issue of *dalit* women cooking food, and villagers and students boycotting the Scheme altogether. In this case, the Cabinet Minister of Andhra Pradesh had to reprimand officers in the district of Karimnagar. This is only one instance, but there are several other instances separate plates and glasses for *dalit* children, allocation of separate lines and separate benches. These are some of the issues reported in newspapers, especially from coastal district of my State of Andhra Pradesh. During our meetings, we took up the case with the district Collectors. Basically, the Scheme is meant for improving attendance in schools and to bring down the dropout rates. The State Governments need to take more interest. Sir, nowadays Governments are laying lots of emphasis, and the hon. Finance Minister also laid stress, on the quality education at the higher level, especially for the students coming from the low social economic background. This Scheme is meant for improving the standards of the people in rural areas. Sir, the other day, the House took pains to discuss various problems being faced by the farming community, the farm workers, and the agricultural labourers. The House would agree with me that the education is the key for progress; it is the key for economic progress; it is the key for social advancement; and it is the key even for cultural progress. That is why the whole philosophy in introducing the Mid Day Meal Scheme is to see that the targeted population makes use of this Scheme. Nutritious food is an important thing not only from the point of view of their health but also in escaping from the burden of child labour. Sir, in the villages, still the students are being sent as wage earners because of the economic conditions. These are the key objectives, but with this

attitude of the Government, with this attitude of the bureaucracy, some times the Schemes does not really go to the needy. Unfortunately, we are not able to do that even through electronic media. When we were children, the impetus was given to national values through radio, and through audio-visual shows in villages. I think we have given up these little relaxations and we are a little complacent in the wake of liberalization, globalization and privatization, Sir, the basic role of the State Government is to promote a homogeneous society. The Central Government cannot say that it is the responsibility of the State. I am not only talking about the implementation of the Mid Day Meal Scheme, but there are also so many other things, which are really meant for the poorer sections. We are not able to get the desired results, because our implementing machinery is not sensitive, is not responsive, to the aspirations and needs of the people. So, in this background, we have requested for this half-an-hour Discussion. The hon. Minister has, especially, indicated which are the States where the scheme has not even taken off. I would request him, through you, that the reasons should be given clearly. We should have a series of discussions with the officers and with the Governments concerned. Sir, those States which are doing better may be encouraged. There is an attitude in the Government of India. Suppose Andhra Pradesh or southern States are doing well in NGO sector or in the socio-economic sector. Then, there is a sort of discouragement. They say other States should also be taken care of. Our initiative should not go against your interest. So, I think, the States which are lagging may kindly be taken up. The States which are implementing this scheme may please be encouraged. The main problem is in UP and Bihar. I had the opportunity of going and looking at the plight of villagers in Bihar and UP. So, really, this scheme needs to be implemented with a greater impetus in these areas because the standards of education of the rural people are very, very poor. Secondly, Sir, the States...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please conclude. You only have to raise the issue.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I only request the hon. Minister that this scheme may be extended up to 10th class because it is yielding results, especially in southern States. There is a lot of improvement in the attendance, there is a lot of improvement in the quality, their punctuality and their performance at the seventh standard. So, seeing the results, at least, those States who had done better may kindly be encouraged and in those States, the scheme may kindly be extended. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. hon. Minister... (*Interruptions*)...After

the Minister gives reply for this...(*Interruptions*)...उसके बाद, you can ask supplementary. That is why I said. Okay, it is only pointed questions. It is no question of lengthy speaking...(*Interruptions*)...भाषण नहीं दीजिए।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : सर, इसमें नाम दिया गया है।

श्री उपसभापति: यहां नाम दिया गया है श्री हनुमंत राव जी।

श्री वी॰ हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन, सर अभी मिड-डे मील स्कीम के बारे में जैसा हमारे सीलम साहब ने कहा, यह सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, स्कूल जाने के वास्ते जितने भी नौजवान गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, बिलो पावर्टी लाइन के शैडयूल्ड कास्ट, ओबीसी, आदि जितने भी बच्चों को पढ़ाने के वास्ते, स्कूल जाने के वास्ते एक तरीका बताया कि गांव में जिन बच्चों को मां-बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजते, जिनसे लेबर का काम कराते हैं, उन लोगों के वास्ते मिड-डे मील स्कीम लाई गई है। अब यह काम सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है। मैं आपको आन्ध्र प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूं। फर्स्ट से फिफ्थ तक 2000 से 2001 तक जितने बच्चे स्कूल गए, नेक्स्ट ईयर इसे बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। अब देखिए, 2000-2001 में यह 89,05,953 है, तो नेक्स्ट ईयर 2001-2002 में 86,26,241 है। सर, यह कितना घट गया है। उसके बाद 2002-2003 में 85,33,631, फिर 2003-2004 में 79,75,659 और 2004-2005 में 76,92,411 है। That means, 13 लाख स्टूडेंट्स कम हो गए। इसकी वजह क्या है, मैं यह बताना चाह रहा हूं। जितने भी मिड-डे स्कूल हैं, वहां राइस सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वह हरियाणा से आता है, पंजाब से आता है या कहीं से भी आता है। यह इतने पुअर क्वालिटी का है कि इसकी वजह से कोई बच्चा वहां खाने के लिए नहीं आता है। इसमें 125 ग्राम राइस एक बच्चे को देने की बात है। उसे 125 ग्राम राइस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि एक आदमी के खाने के वास्ते राइस का जो खर्च आता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है। वह 125 पैसे एक आदमी के वास्ते देती है।

श्री उपसभापति: सवाल पूछिए न।

श्री वी॰ हनुमंत राव: सर, उसी से सम्बन्धित सवाल पूछ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एक स्टूडेंट को 125 पैसे देने की बात है, वह कम पड़ रहा है। जो पकाने वाले लोग हैं, जो लेडीज़ आर्गेनाइजेशंस हैं, डाकरा ग्रुप्स हैं, ये लोग क्या करते हैं ...।

सर, ये लोग पैसा बचाने के लिए दाल में पानी डाल देते हैं, जिससे खाना नर्म बनता है। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

सर, यहां दिल्ली में एन॰डी॰एम॰सी॰ के स्कूल में 100 ग्राम दे रहे हैं, एक स्टूडेंट को 2 रुपए दे

रहे हैं जब तक आप स्टूडेंट के ऊपर खर्चा नहीं बढ़ाएंगे तब तक पकाने वाले भी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। सर, मैं एक incident बताना चाहता हूं। हमारे स्टेट में गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर अपनी कांस्टीटुएंसी में, नक्सलाइट एरिया के करीमनगर में गए और हैड मास्टर को जाकर पूछते हैं कि बच्चे कम क्यों आ रहे हैं? वह बोलता है कि सर, पकाने वाली ये लेडी शेडयूल्ड कास्ट की है, इस वजह से अपर क्लास के बच्चे खाने को नहीं आते हैं। मिनिस्टर साहब ने फिर पूछा कि कितने बच्चे आ रहे हैं? उन्होंने बताया कि 200 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 25 बच्चे बैठे हैं, बाकी के 175 नहीं आए। जब तक यह महिला पकाती रहेगी, कोई भी खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आप देखें कि आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी देश में हरिजनों के प्रति छुआ-छूत की प्रथा चल रही है। It is really unfortunate. फिर वहां का मिनिस्टर बोलता है कि मैं नक्सली लोगों को बोलूं, अन्ना लोगों को बोलूं, तुम हैड मास्टर सुनते हो। आप देखें एक मिनिस्टर कितना डाउन हो गया है? तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वह कह रहे हैं कि नक्सलाइट को बोलें, इस से ज्यादा बेइज्जती क्या है? इसलिए मैं हमारे मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि स्टूडेंट के लिए ज्यादा पैसा दें, चावल बढ़िया दें और पकाने वाले के ऊपर सुपरवाइज़र रखें। आप के एम॰आर॰ओ॰ से कुछ नहीं होता है। वह एक दिन आता है, फिर चला जाता है। गांवों के बड़ें लोगों के ऊपर अगर जिम्मेदारी डालें तो बच्चों को खाना बराबर मिल सकता है। यही मेरे सुझाव हैं।

श्री उपसभापति: श्री नंदी येल्लैया।

श्री नंदी येल्लैया (आंध्र प्रदेश): माननीय डिप्टी-चैयरमैन सर, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने मिड डे मील स्कीम के बारे में काफी चर्चा की। सर, यह मिड डे मील एक अच्छा प्रोग्राम है, जो रूरल एरियाज के अंदर आज भी गरीबी की रेखा के नीचे के विद्यार्थियों के लिए एक सहारा है। इस से उन को खाने का सहारा मिलता है। उनके लिए यह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस स्कीम में पकाने का काम DWKRA ग्रुप वाले करते हैं। यह एक ऑनरेरी जॉब है।

श्री उपसभापति: आप सवाल कीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सर, मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपसभापति: सुझाव मत दीजिए, सवाल कीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सर, इस स्कीम में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। There is no boring of wells in schools. सर, आप जानते हैं कि आज पानी की कमी के अलावा पानी के अंदर 75 परसेंट पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। मैं ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं जहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए, ऐसी तमाम बातें हैं। मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कहूंगा कि जैसे अभी सीलम जी ने भी कहा हमारे देश में मिड डे मील में कई जगह बहुत-सी शिकायतें हैं। कई जगह बारिश के मौसम में, खाना पकाने के लिए गैस के सिलिंडर की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पकाने की जिम्मेदारी दो आदमियों को दी जानी चाहिए।

यह जो पकाने का सामान राइस और वेजीटेबल्स हैं, उनके बेट बढ़ाए जाने चाहिए। उनका वजन सही तरीके से होना चाहिए। एक और बात है, अभी हमारे हनुमंत राव जी ने कहा हमारे यहां DWKRA ग्रुप की महिलाएं खाना पकाती हैं। आज भी हमारे देश के अंदर कुक की जाति को लेकर छुआ-छूत की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस स्कीम में दलित और हरिजन कुक्स को ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। कि वह कोई बैकवर्ड क्लास है, वह अछूत है। इस तरह की feeling होना गलत है। सर, ऐसे लोगों को punishment होना चाहिए। वहां स्कूलों में पीने के पानी के लिए बोरिंग वेल्स का इज़ाफा किया जाए, मिड डे मील में खाने की क्वालिटी सुधारी जाए और छुआ-छूत का मसला खत्म किया जाए। आखिर, हमारे देश के अंदर जाति अनुसार यह अलग से पकाने की बातें कब तक चलेंगी, यह बंद होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग मंत्री जी बैठे हुए हैं। आप इसकी समीक्षा कीजिए। पूरे राष्ट्र को बताइए कि मिड डे मील का सिस्टम किस तरह से लागू हो रहा है? इसको पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए, छुआछूत का जो ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: डा॰ प्रभा ठाकुर। ...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और बारिश से बचाव के लिए वहां कोई किचन-शेड नहीं है। वे लोग भोजन कैसे पकाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी क्वालिटी इम्प्रुव कीजिए। इसमें जो तमाम त्रुटियां हैं, जहां पर ...(**व्यवधान**)... आज भी दलितों कुक्स या छात्रों के साथ जो अनटचेबिलिटी की बातें हो रही हैं, इसे आप बंद कीजिए।

श्री उपसभापति: डा॰ प्रभा ठाकुर।

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति जी। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगी।

श्री उपसभापति: आप सवाल कीजिए।

डा॰ प्रभा ठाकुर: केवल दो मिनट, उपसभापति जी। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों विशेषकर जो कमजोर तबके के स्टुडेंट्स हैं, जो गरीब हैं, कमजोर वर्गों से आते हैं,उनको प्रेरित करने के लिए मिड डे मील की स्कीम बहुत अच्छी है। जैसाकि मेरे पूर्व साथियों ने भी बताया कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के बजाए, इसमें गिरावट आई है। इसकी जो वजह है, वह दूर होनी चाहिए। सरकार ने जिस उद्देश्य से मिड डे मील की योजना बनाई है, यह पूरी योजना उसी रूप में

लागू होनी चाहिए ताकि इससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो, इसमें गिरावट न आए। मैं उसके लिए यहां कुछ बातें रखना चाहूंगी। एक बात तो यह है कि एक बार राजस्थान में भी यह प्रकरण बहुत चला था कि बच्चों को एक्सपायरी डेट का टिन्ड फूड दिया जा रहा था। इस पर बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद उन्हें हेल्थ फूड देने की बात आई। बच्चों को वैसा खाना दिया जाना चाहिए, जो उनकी रुचि का हो और जिसे वे स्वाद से खा सकें। जैसे-दलियां या घुघरी या साउथ में चावल का प्रचलन है, तो वहां चावल। मेरा एक निवेदन यह है कि एक तो बच्चों को उस क्षेत्र में, उस राज्य में कौन-सी रुचि का फूड चलता है, यह देखते हुए उन्हें दिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि वह खाना एक्सपायरी डेट का नहीं हो, खराब नहीं हो, ऐसा न हो कि उसमें घुन लग गया हो या जाले लग गए हों। इसके मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कि कहीं इस तरह का भोजन बच्चों को स्वस्थ करने के बजाय उनको बीमार न कर दे। एक अन्य बात यह है कि हर राज्य में, पर-हेड बच्चों के लिए जो राशि दी जाती है, वह बराबर होनी चाहिए, उसमें कहीं भी राज्य-वार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं एक बात यह कहना चाहूंगी कि वहां स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही ईंधन की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा है। राजस्थान में भी हमने एक ऐसा मामला सुना कि (**समय की घंटी**) उस अनाज से, गुड़ से, घी से अध्यापक महोदय का भी अपने घर का राशन-पानी चल रहा है या औरों का भी चल रहा है। यह सब नहीं होना चाहिए। यह पूरी राशि जिस निमित्त दी जा रही है, वह स्टुडेंट के लिए ही, विद्यार्थियों के लिए ही काम में लाई जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यों, यह हाफ एन ऑवर डिस्कशन है। 20 मिनट हो गए हैं। आप क्वेश्चन पूछिए। हर सदस्य अगर भाषण करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: उपसभापति जी, यह भाषण नहीं, सुझाव है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, हाफ एन ऑवर ...(**व्यवधान**)... अच्छा ...(**व्यवधान**)... श्री राममुनी रेड्डी ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति जी, बच्चों के फूड पर तो ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: आप तो व्यक्तिगत बातें बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is an important issue to be discussed widely. ...*(Interruptions)*... It is a good programme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put questions only.We are not having another discussion on this issue.

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: We have to think thoroughly

and implement it properly because in some areas we are not having proper school building. ...*(Interruptions)*... In many areas, there are no proper school building, but we are implementing this Food Programme! It is a good programme in my view. But we have to consider some points also. We have to build kitchens. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: क्यों साहब, आप मिड डे मिल की बजाए ...(व्यवधान)...

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: We have constructed some kitchens, and through DWCRA groups we have implemented it. Weekly once, we were giving an egg. Now, they are not giving! I suggest our Minister to give nutritious food, at least, weekly once one egg, through the National Egg Coordination Committee Through that Committee we can provide there are so many eggs we are getting. This Government is providing 50 per cent subsidy for transporting the materials, rice, etc., from godowns to the schools. It has to be fully subsidised. Full transportation charges should be given. This has to be considered by the Minister.

Another point is that the conversion charges should also be increased. Now we are levying an educational cess of two per cent on oil, diesel and other things. This has to be increased further by one per cent or 0.5 per cent.

Another thing is that cooking has to be done properly and in hygienic conditions. The DWCRA groups have to be encouraged. There are so many Self-Help Groups. They should be encouraged. These points have to be considered by the Minister. Thank you.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to put on record in this House that it was my State of Tamil Nadu which had introduced, for the first time, in independent India, the Mid-Day Meal Scheme for the school-going children.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It was done by Mr. Kamaraj.

SHRI P.G. NARAYANAN: Yes.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: He only said that "his State", not his party. Kamaraj was from Tamil Nadu.

SHRI P.G. NARAYANAN: When this Scheme was introduced in the fifties, it had some deficiency. It was for a very limited section of the children. A fresh impetus was given to it by late Dr. M.G. Ramachandran

and he expanded the Scheme in a big way to cover all school-going children. He also laid emphasis on the nutritional aspect of the meal by including seasonal vegetables and eggs. Thousands of schools in Tamil Nadu are maintaining a full-fledged kitchen and efficient machinery to provide steaming hot food to school-going children. When the Scheme was expanded by Dr. M.G. Ramachandran in the eighties, the opposition parties in the State attacked him by saying that this Scheme was not feasible and ridiculed him. *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, what is the information that you want to get from the hon. Minister? *(Interruptions)...* What is the information that you want to get from hon. Minister? *(Interruptions)...* This is a Half-an-hour Discussion. *(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: He is making a political statement.

SHRI P.G. NARAYANAN: Our Puratchi Thalaivar M.G. Ramachandran was a determined man and he implemented the Scheme successfully, and the result was that the school-going children studied with full confidence. The Scheme had the salutary effect of preventing school dropouts and made a dent on child labour. I can say, without any fear of contradiction, that Tamil Nadu has the lowest dropouts in whole India thanks to the successful implementation of the Scheme. Our present Chief Minister, Puratchi Thalaivi, is also committed to carrying forward this Scheme... *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you put your questions to the hon. Minister, Mr. P.G. Narayanan.

SHRI P.G. NARAYANAN: ...which was introduced by her political mentor, Dr. M.G. Ramachandran. When this Scheme was introduced for the first time by Dr. M.G. Ramachandran, the cost was only Rs. 100 crores. After it was expanded by the State, now it comes to Rs. 1,000 crores. Our Chief Minister has toned up the nutritious aspect of this Scheme. *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you have any questions to put to the hon. Minister? *(Interruptions)...* Have you got any questions to put to the hon. Minister? *(Interruptions)...*

SHRI P.G. NARAYANAN: Yes, I will put. *(Interruptions)...*

Why are you not allowing me? *(Interruptions)...*

You are allowing others. *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a Half-an-hour Discussion. This is not a debate. *(Interruptions)*... This is a Half-an-hour Discussion. You have to put questions to the Minister. I was saying this to everybody. *(Interruptions)*... You please conclude. *(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: Why are you interrupting? *(Interruptions)*... This is not good. *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Natchiappan, I am worried... *(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: I would like to appeal to all the State Governments to look at the Mid-Day Meal Scheme in operation in Tamil Nadu. It is a very successful scheme . I also urge upon the Central Government to bear the entire cost which Tamil Nadu is incurring on this scheme because Tamil Nadu is already overburdened. Sir, the Central Government is collecting Education Cess at a rate of two per cent, but after collecting a huge amount, they are spending a very small amount. Therefore, I demand that this fund should be enhanced substantially to make it more useful and successful. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल: माननीय उपसभापति जी, चूंकि आपने कहा कि सिर्फ सवाल पूछिए, तो मैं अपने को वहीं तक महदूद रखूंगा। महोदय, इस योजना को बहुत ही पवित्र उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका लाभ भी बच्चों को बहुत मिला है, खास तौर से जो गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह स्कीम मुश्किल से 60 प्रतिशत सफल हो पाई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से राज्य हैं, जहां से इस स्कीम के बारे में सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं? सबसे ज्यादा पिल्फ्रेज किन राज्यों में है, और क्या वहां कोई मोनिटरिंग एजेंसी लगाने का विचार है? इस तरह की मोनिटरिंग एजेंसी लगाई जाए, ताकि जो गरीबों का खाना है, बच्चों का खाना है, उसे लेकर लोग करोड़पति न बनें, उसमें भ्रष्टाचार न हो, क्योंकि इस तरह की शिकायतें बहुत हैं।

दूसरी बात यह है कि फूड कुकिंग को लेकर यह बहुत जबरदस्त बात उठ रही है कि इसे पकाने का बहुत झंझट रहता है और यह बात सही भी है कि कहीं आप दाल-चावल लाओ फिर उसे पकाओ, बनाओ, उसमें बहुत झंझट रहता है। क्या पैक्ड फूड का सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता? आजकल तो पैक्ड फूड इतना आ रहा है कि आप बस उसे एक मिनट में गर्म कर सकते हैं और उसी को तुरन्त दिया जा सकता है। कई जगह बिस्किट देने की परम्परा भी है, हालांकि यह बिस्किट कागजों पर ही दिए जाते हैं और बच्चों तक नहीं पहुंचते हैं या पता चलता है कि इतने टन बिस्किट कागजों पर खरीदे गए और इस प्रकार स्कूलों तक कुछ ही पहुंच पाते हैं इसलिए मेरा

सुझाव है कि पैक्ड फूड इस्तेमाल किया जाए या बिस्किट दिए जाएं अथवा कुछ और इसी प्रकार का दिया जाए ताकि पकाने का झंझट खत्म हो जाए।

तीसरी बात यह है कि न्यूट्रिशियस फूड को लेकर जो स्कीम्स हैं, उनके लिए भी जगह-जगह से तमाम शिकायतें आ रही हैं। मंत्री जी क्या यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे अधिक शिकायतें कहां से आ रही हैं और उन पर कार्यवाही करने की उनकी क्या योजना है?

चौथी बात यह है कि मेरा अपना विचार है कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे सुधार करके लागू करना चाहिए और अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर पूरे देश में अपने ढंग से कोई ऐसी मोनिटरिंग एजेंसी लगाता है, तो निश्चित रूप से इस स्कीम को बहुत ही कारगर बनाया जा सकता है। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय उपसभापति जी, मैं अपनी बात की शुरूआत उर्दू के प्रसिद्ध अदीब और चिन्तक सरदार ज़ाफरी जी के प्रश्न से करूंगी, क्योंकि आप लगातार प्रश्न पर ही आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं की पंक्तियों में प्रश्न पूछना चाहूंगी।

श्री उपसभापति: जी हां, कविता में ही प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी:

"मां रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ़ सूती मिल में है।
कोख से मां के जब से जन्मा है, बच्चा खोली के काले साए में है।।
जब यहां से निकल के जाएगा, कारख़ानों के काम आएगा।
अपने मजबूर पेट की ख़ातिर, भूख सरमाए की बढ़ाएगा।।
यह जो नन्हा है, भोला-भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है।
पूछती है यह ख़ामोशी, कोई मुझे बचाने वाला है?"

उपसभापति जी, आज़ादी के 58 वर्षों के बाद भी इस नन्हें, भोले-भाले जीवन के इस प्रश्न का हम संतोषजनक कोई उत्तर दे नहीं पाए हैं। आज भी हमारे देश का बचपन क्यों कभी चाय के प्याले धोता हुआ, कभी घरों में रोटियां सेंकता हुआ, कभी चूड़ियां बनाता हुआ, कभी पटाखे बनाता हुआ, कभी पशुओं को चराता हुआ, कभी कूड़ा बीनता हुआ नज़र आता है? आज भी ऐसा क्यों है कि हमारे देश के करोड़ों बच्चे स्कूल के प्रांगण के बाहर हैं? संविधान में घोषित सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य अभी भी हमसे कोसों दूर क्यों है? एक लोकतांत्रिक जनकल्याणकारी राज्य के फर्ज़ को हम अब तक क्यों नहीं अदा कर पाए हैं?

हालांकि, उपसभापति जी, हमसे बड़ा योजनाधर्मी और कोई नहीं है, लेकिन योजनाओं की असलियत क्या है? अगर हम योजनाओं की असलियत को देखें तो मुझे कहना पड़ता है कि-

"हमें बड़े बलिदान से आज़ादी मिली।
नेता मिले, चरखा मिला, खादी मिली।।
और योजनाओं से दबे-दबे जो देखा।
तो पहले से बीमार आबादी मिली।।"

उपसभापति महोदय, भारत के स्कूली बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की जो एक बहुउद्देश्यीय योजना लागू की गई थी इस योजना का बहुत गहरा संबंध हमारे देश की प्राथमिक, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था से है और जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते तो स्कूल को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए और यह जो योजना थी वह उसी का एक अंग थी कि किसी तरह हम बच्चों को स्कूल में ले जाएं, बच्चे स्कूल की ओर जाने के लिए आकर्षित हों, इसीलिए कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भर्ती हो, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हो और इसके अलावा इसके जरिए जो एक सामाजिक उद्देश्य हम हासिल करना चाहते थे और जिस प्रश्न को मूल वक्ता ने उठाया, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज भी यह जो इतनी बहुकोणीय योजना लागू की गई, वह योजना सफल नहीं हो पाई। मुझे अमर्त्य सेन याद आते हैं। उन्होंने कहा था और मैं विशेषकर मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि अमर्त्य सेन ने कहा था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा संसाधनों की कमी के कारण असफल नहीं हुई है, बल्कि उससे ज्यादा असफल इस कारण से हुई है कि हमारा प्रबंधन ठीक नहीं था, हमने संसाधनों का सही रूप से संगठन नहीं किया था और यही कारण इस योजना की भी असफलता का है। उपसभापति महोदय, हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए सहायता दी जा रही है, प्रति क्विंटल अनाज की ढुलाई के लिए 50 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके बावजूद सभी राज्यों में यह योजना लागू नहीं हो पाई है। तो क्या मंत्री जी, आपने इस योजना का कभी सर्वे किया है कि आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं आपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर, इस योजना का सर्वेक्षण किया? जहां तक राज्यों की हालत है, उपसभापति महोदय, राज्य कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार की तरफ से जितना पैसा मिलता है वह पैसा पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी इतना खर्चा लगता है कि हम इस योजना को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि पहली बात तो वे यह करें कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों या शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाकर, इस बात की जांच करें कि विभिन्न राज्य सरकारें जो इस योजना पर अमल कर रही हैं, इस योजना के अमल के रास्ते में कौन-सी रुकावटें आ रही हैं, उनका कितना अतिरिक्त खर्चा आ रहा है और वह अतिरिक्त खर्चा केन्द्र सरकार मुहैया कराए। अब जबकि केन्द्र सरकार ने शिक्षा पर दो प्रतिशत का सेस् लगाया है, वह खर्चा क्यों नहीं इस योजना पर लागू किया जा सकता? उपसभापति महोदय, इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न है, क्योंकि आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि भोजन नहीं शिक्षा चाहिए। वे लोग, वे पत्रकार, जो हमारे देश की मौजूदा यथार्थ

से, वस्त-यथार्थ् क्या है उससे परिचित नहीं हैं, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तरह ही आलोचनाओं के फंदे में मत पड़िए, भोजन चाहिए और भोजन के साथ शिक्षा चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे छात्रों के दिलो-दिमाग में, अभिभावकों के दिलो-दिमाग में कतई यह धारणा नहीं जानी चाहिए कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के तहत जो भोजन दिया जा रहा है वह दूषित भोजन है, उसमें पर्याप्त कैलोरी नहीं है, इसलिए एक तो इस बात को ध्यान रखिए और दूसरे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था कि हर छात्र को हर स्कूल में 200 दिन भोजन की व्यवस्था निश्चित रूप में होनी चाहिए, पके हुए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें 300 ग्राम कैलोरी और 12.8 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ये जो बातें हैं इनकी ओर मंत्री जी ध्यान देंगे और मैं आशा करती हूं कि इस बहुकोणीय योजना को सफल बनाने में सारी कोशिशें करेंगे। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, we are discussing about the Mid Day Meal Scheme. It was an idea initially conceived by the great Shri Kamaraj, when he was the Chief Minister of Tamil Nadu...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to be brief.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will take one minute only. I would like to tell you how this scheme came into existence. When Shri Kamaraj visited the rural areas, he saw the children grazing cattle there. They did not even have a shed for them. Kamarajji said, "Why are you not going to school? Why are you grazing cattle here?" They said, "We do not have food to eat. Our parents have sent us for grazing the cattle". He said, "If you are given food to eat, will you go to the school?" They said, "Yes, we will go to school". Thereafter, within a month, Kamarajji started the Mid-day Meal Scheme in schools in Tamil Nadu and, thereafter, attendance of students in schools had increased. Thereafter, that scheme had been implemented throughout the country. That is what I want to say.

Now, the first question that I want to ask is this. Before that I would like to say that the allocation per student for nutritious food has to be increased. I want to know from the Minister whether the Government is thinking of increasing the allocation for various States on the basis of students who have been in the schools. Secondly, in our State, we are giving the morning breakfast, which includes bread and milk, to students, and it is known as the Rajiv Gandhi Breakfast Scheme. We are implementing that scheme throughout the State. We are spending more than one crores of rupees for that scheme alone. I would like to know whether the Government would implement that morning breakfast scheme to further improve the enrolment of children in schools. In the Northern States,

especially, the number of drop-outs is more. So, for bringing down the number of drop-outs in schools, will you consider inclusion of this morning breakfast scheme? Thirdly, this year, from the month of August, we are going to give hot milk to children in the evenings after play. Ours is a small State. We are implementing it as a model scheme. Then, I would like to know from the hon. Minister whether he has received any complaints about the misuse of funds on the Mid-day Meal Scheme by any State Governments.

श्री उपसभापति: श्रीमती जमना देवी बारूपाल। आप केवल सवाल कीजिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान): सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय उपसभापति जी, इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है, फिर भी यह चर्चा अधूरी लगती है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रांतों में, भिन्न-भिन्न राजनेताओं पर कई प्रश्न-चिन्ह लग जाते हैं। जो भी इस योजना में बच्चों के लिए दिया जाता है, वह बहुत कम मात्रा में होता है और वह प्रोटीनयुक्त नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मिड डे मिल में जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, एक नम्बर। दूसरी बात यह है कि उत्तरी राज्यों की बात कई माननीय सदस्यों ने कही है। मैं आपसे बहुत ही नम्र शब्दों में आग्रह करूंगी कि राजस्थान ऐसा प्रांत है, अन्य प्रांतों के साथ उसके आंकड़े उठाकर देखेंगे, तो पायेंगे कि शिक्षा कि दृष्टि से यह सबसे पिछड़ा प्रांत है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं आज भी साक्षरता में बहुत कमजोर हैं। मैं तो पांच साल पहले प्रधान रही हूं और प्रधान के टाइम में मैंने उनको बहुत गा-गाकर के सुनाया,

"उठो, जागो ए बहनों, पढ़ लिख लो,
जो जाग गई सो पढ़ लिख ली,
जो सोइ गई, वह पछतावत है।
अज्ञान की अंखियां खोल जरा,
तू अनपढ़ क्यों कहलाती है।"

कहने का मतलब यह है कि मैंने तो बहुत प्रयास किया है, जब जाकर के पूरे राजस्थान में अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जीरो से प्राईमरी तक की शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसी हालत में, जो प्रांत बहुत ज्यादा अशिक्षित हैं और शिक्षा में बहुत पीछे रह गये हैं, उनकी तरफ, उनके बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जीवन-स्तर भी दूसरे के बराबर उठ सके।

दूसरी बात यह है कि स्कूली बच्चों को जो पोषाहार दिया जाता है, उसे हमें देखना है कि क्या वह सुचारू रूप से, नियमित रूप से बच्चों को दिया जाता है? और क्या जो पोषाहार है, वह स्वच्छ और पोष्टिक है क्योंकि मैंने दो साल पहले एक केन्द्र में जाकर- मैं गांव में बहुत ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यह सवाल हो चुका है। इसका जवाब आएगा। ...(**व्यवधान**)... यह सवाल कर चुके हैं।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: एक मिनट, सर। मैं बहुत घूमती हूं इसीलिए मैंने वह केन्द्र देखा। जब मैंने वह केन्द्र देखा तो मैंने उस केन्द्र में क्या पाया – आप तो कह रहे हैं, चावल देंगे, दूध देंगे, ब्रैड देंगे, पता नहीं कितनी आइटमों को आपने गिनती में लगाया – लेकिन मैंने वहां क्या पाया ...(**व्यवधान**)... एक मिनट भाई साहब, मैं बीच में भूल जाती हूं, मैंने वहां यह देखा कि जैसे गाय, भैंस को घास में आटा मिलाकर देते हैं, जब वह लिक्विड हो जाता है ...(**व्यवधान**)... एक मिनट सर, आप मुझे जरा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: जरा उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: जो आटा होता है, उसको गीला करके उस घास में मिलाते हैं, जहां पर हरा चारा गाय-भैंस को कम मिलता है। वह आटा पतला-पतला करके उसे दे देते हैं और उस आटे की सुगंध से वह सूखा घास गाय खा लेती है। मैंने जब वह आटा देखा तो मुझे वह बहुत बदबूदार लगा। मैंने उन्हें कहा, बहन जी, यह थोड़ा-सा आटा मुझे भी दे दो, मैं भी टेस्ट करूंगी कि इसका स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लग रहा है। वह यह नहीं समझी कि यह आगे जाकर शिकायत मेरी कर देगी और उसने मुझे एक कड़छी भरकर आटा दे दिया। मैंने उसे घर में लाकर कलैक्टर को बताया। मैंने कहा कि ये तो जन्म से ही अपंग हैं, जन्म से ही ये शोषित हैं, जन्म से ही इन्होंने देखा नहीं (**समय की घंटी**) ऐसा आटा तो कोई भिखारी भी दे देगा।

श्री उपसभापति: आप भाषण नहीं करिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: एक मिनट सर, मैंने कहा, आप इनको और ज्यादा मंगते क्यों बना रहे हो, कागजों में आटा दे देकर? सर, एक तो मेरा आपको यह सुझाव है कि इन बच्चों को स्कूलों में जो कुछ भी खाने को दिया जाए, बड़ी तमीज से, बड़े सलीके से, बड़े प्यार से देना चाहिए और छोटे मोटे बर्तन में देना चाहिए। आज स्टील के बर्तन, आप खारी बावली में जाकर देखिए, सत्तर-अस्सी रूपए किलो में आएंगे और अगर एक हजार रुपए के बर्तनों को इकट्ठा करते हैं (**समय की घंटी**) तो बोरा भरकर बर्तन आएंगे। आप क्यों कंजूसी करते हैं?

श्री उपसभापति: अब समाप्त करिए। श्री मूल चन्द मीणा।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: सर, एक मिनट, ये तो बहुत अच्छे मुद्दे हैं।

श्री उपसभापति: मुद्दे तो अच्छे हैं, लेकिन वक्त भी देखना है।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: उनको बर्तनों में खाना देना चाहिए ताकि वे जाने तो सही। जैसे आप एक पक्षी को पिंजरे में डाल देते है, न वह उड़ना जानता है, न कुछ और जानता है और एक तोते को लाकर बोलते हैं कि राम-राम बोल तो वह सारी बातें भी बोल देता है, चिट्ठियां भी पकड़ा देता है। यही हालत उन बच्चों की होती है जिनको प्रारम्भिक शिक्षा नहीं मिलती।

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: सर, मैं जवाब ही मांग रही हूं।

श्री उपसभापति: जवाब देंगे। मंत्री जी जवाब देंगे। आप बोलिए मीणा जी।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: सर, मैं थोड़ा-सा और कहना चाहती हूं। मेरा कहने का मतलब था ...(व्यवधान)... मैं अभी समाप्त करती हूं। सर, मैं जो बात कहना चाहती थी, वह भूल गयी। ...(व्यवधान)... अभी छूआछूत इतनी है कि 58 वर्ष के बाद भी हम जब जाते हैं तो — मैं कुछ और कह दूंगी* कहने से बहुत बुरा होता है, आजकल डंडा लेकर मारते हैं लेकिन बाल्मीकि सभ्य शब्द है, उसको कहना अच्छी बात है — वह बाल्मीकि महिला जो कि वहां उस पोषाहार के अंदर थी और तहसील विजयनगर, जिला गंगानगर में वह कार्यकर्ता थी, वह एम॰ए॰ पास थी, उस लड़की को ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्या कहना चाहती हैं? यह हाफ एन ऑवर डिसकशन मिड डे मील पर है। आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: मैं कह रही हूं सर, कितने मुद्दे हैं, यह कितने अच्छे मुद्दे हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं होगा।...(व्यवधान)... कितना समय लेंगी आप? मीणा जी आप बोलिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: छुआछूत के चलते उसको नौकरी से निकलवा दिया ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मीणा जी, आप बोलिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: अगर आपकी सबकी अच्छा है तो चर्चा बंद कर देते हैं।

श्री उपसभापति: इच्छा नहीं, वक्त भी देखना है।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: लेकिन मुद्दे इतने काम के हैं जो सबकी नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैं डायरैक्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मिड डे मिल एक अच्छी स्कीम है लेकिन माननीय मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न है कि राज्य-वार कितना अनाज आपने राज्यों को दिया है और किस-किस राज्य ने उसका सदुपयोग किया है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह भोजन सामग्री में घटिया किस्म की सामग्री स्टेट वाइज़ पकड़ी गयी हैं, कितने लोग इसमें इनवॉल्व पाए गए हैं, कितने टीचर्स, कितने दूसरे काम करने वाले अधिकारी और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? तीसरा, इसकी मॉनिटरिंग की शिकायत सब जगह से आयी है। सब स्टेट्स में मॉनिटरिंग की कमी है।

इसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, यह मुझे बताएं। धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सर, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा। श्री हनुमंत राव जी के जरिए एक बड़ी ही अहम बात हाऊस में आई है कि कुकिंग करने वाली एक दलित महिला की वजह से अपर कास्ट के बच्चे खाने नहीं आते। तो मैं वजीर-ए-मोहतरम से यह

* Not recorded.

जानना चाहूंगा कि इस खतरनाक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हुकूमत क्या कदम उठाएगी और इस तरह के और भी कितने वाकयात पूरे मुल्क से आए हैं, उसकी भी जानकारी हमें दे दें, तो बेहतर होगा और इसे खत्म करने के लिए क्या कोई समयबद्ध योजना बनाकर इस बात का आश्वासन देंगे कि बहुत जल्द हम सुनें कि ये चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हैं और हर हिंदुस्तानी को बराबरी का सम्मान दिया गया है और एक साथ छुआछूत को खत्म करके तरक्की की राह पर डाला गया है?

[مولانا عبیداللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش" : سر، میں صرف ایک سوال کرنا چاہونگا۔ شری ہنومنت راؤ جی کے ذریعہ ایک بڑی ہی اہم بات ہاؤس میں آئی ہے کہ کٹنگ کرنے والی ایک دلت مہیلا کی وجہ سے اپر کاسٹ کے بچے کھانا کھانے نہیں آتے۔ تو میں وزیر محترم سے یہ جاننا چاہونگا کہ اس خطرناک پرابلم کو ختم کرنے کے لئے حکومت کیا قدم اٹھائے گی اور اس طرح کے اور بھی کتنے واقعات پورے ملک سے آئے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہمیں دیدیں تو بہتر ہوگا اور اسے ختم کرنے کے لئے کیا کوئی سے بڈ یوجنا بنا کر اس بات کا آشواسن دیں گے کہ بہت جلد ہم سنیں کہ یہ چیزیں مکمل طور پر ختم ہوگئی ہیں اور ہر ہندستانی کو برابری کا سمان دیا گیا ہے اور ایک ساتھ چھوا چھوت کو ختم کر کے ترقی کی راہ پر ڈالا گیا ہے؟]

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, यह मिड-डे मिल की जो योजना है, यह बहुत ही अच्छी योजना है। गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते या बीच में ही स्कूल छोड़ देते है, उसका एक कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी होती है और यह योजना गरीबों के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस योजना को तो निश्चित रूप से बनाए रखना चाहिए और जो आर्थिक सहायता है, उसको बढ़ाना चाहिए। कभी-कभी शिकायतें आती हैं, बच्चे भोजन खाकर बीमार पड़ जाते हैं या जो स्तरीय भोजन होना चाहिए, वह उनको नहीं मिलता है। खास करके, गांवों में जो स्कूल हैं, उनमें तो पढ़ने के लिए भी अच्छा भवन नहीं होता है, खाना बनाने के लिए जगह की कमी रहती ही है। कभी-कभी तो जो बच्चे होते हैं, उनको खाना बनाने में लगा देते हैं। उनको पौष्टिक भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, इसके लिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। भोजन के लिए जो सामान बाजार से खरीदा जाता है, उसकी भी शिकायत मिलती है कि स्तरीय सामान नहीं खरीदते, घटिया सामान खरीदते हैं। भोजन की मात्रा भी कम दी जाती है- ये सब शिकायतें मिली हैं। मैं समझता हूं कि अगर मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था हो, तो यह एक बहुत अच्छी योजना है। एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऊपर से नीचे तक, जिसमें किसी भी स्तर पर इस योजना का दुरूपयोग न हो। स्कूल का स्टाफ हो या खाना बनाने वाले हों, इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें - वह किस प्रकार होगा - वह मैं मंत्री जी पर छोड़ता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस दिशा में कार्यवाही करें, धन्यवाद।

[ ] Transliteration in Urdu Script.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): उपसभापति महोदय, सभी सम्मानित सदस्यों ने इस योजना के औचित्य पर कोई भी प्रश्न-चिन्ह नहीं लगाया और इसे चालू रखने की राय दी, यह अपने आप में बहुत ही उत्साहवर्द्धक चिन्ह हैं। जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली से ऐसी योजनाओं की मॉनिटरिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए इस स्कीम की मॉनिटरिंग और इंप्लिमेंटेशन की जिम्मेदारी मूलत: प्रदेश शासनों की है। वहां पर चाहे वह पंचायत राज के माध्यम से हो या और किसी व्यवस्था से हो, उस स्तर पर प्रादेशिक शासन को ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं यह कह सकता हूं कि इस जिम्मेदारी को सभी प्रदेशों के शासन महसूस भी कर रहे हैं और उन पर अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह बात सही है कि तमिलनाडु में और दक्षिण के राज्यों में, उत्तर के राज्यों से बेहतर मॉनिटरिंग हुई है और इम्पलीमेंटेशन भी हुआ है और उसी का नतीजा है कि ड्रॉप आउट का रेट भी दक्षिण भारत में कम है और उत्तर भारत में ज्यादा है। लेकिन अब इस योजना के बारे में अगर हम एकांगी विचार करेंगे तो इसकी सफलता पर बहुत प्रश्नचिन्ह लगे हैं। अगर राज्यों के शासन और जितनी अन्य व्यवस्थाएं हैं, हम सब मिलकर इस योजना को कार्यान्वित करें तो निश्चित रूप से यह योजना एक अत्यंत लाभकारी योजना हो सकती है। एक प्रश्न यह सामने आया है ओर शायद इस भावना को बल मिला कि आज भी छुआछुत की वजह से इस योजना के अमल में आने में दिक्कत है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं तो कई राज्यों में घटी हैं, आन्ध्र प्रदेश का एक उदाहरण दिया गया, लेकिन अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो ये घटनाएं इतनी थोड़ी हैं, जिससे इस पूरी स्कीम के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस बात का प्रमाण है कि यह देश का समाज इस छुआछुत की बात को उतना ही हेय दृष्टि से देखता है, जितना कि शिक्षित लोग देखते हैं। जो आंध्र प्रदेश में यह घटना हुई है, वहां पर इसका यह असर हुआ कि उस ग्राम के सभी नागरिकों ने यह फैसला किया कि हम सामूहिक भोजन करेंगे और यह बताकर करेंगे कि खाना बनाने के लिए अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिलाएं होंगी। फिर देखेंगे कि खाने के लिए कोई आते हैं या नहीं? यह कितनी सुखद बात है कि उस भोजन को करने के लिए गांव के 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग आए। यह हमारी चेतना का एक उदाहरण है, लेकिन अगर कम लोग भी नहीं आए तो हमें उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न अब बाधा के रूप में, इस स्कीम में नहीं आ रहे हैं। जहां आएंगे, उस पर कार्यवाही होगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि किन राज्यों में यह स्कीम नहीं चल पा रही हैं, अब यह एक आश्चर्य की बात है कि पंजाब और हरियाणा, गोवा और महाराष्ट्र ये तो प्रगतिशील प्रदेश है, वहां पर भी यह स्कीम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इनके सबके अलग-अलग कारण हैं। उन कारणों पर विचार किया जा रहा है। प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों की पिछले अक्टूबर में बैठक हुई थी। वहां पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों में यह आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीने के बाद रिव्यू होगा तो निश्चित ही, हमें इसमें आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। उपसभापति महोदय, यह बात अपनी जगह सही है कि ड्रॉप-आउट रेट करीब-करीब सभी प्रदेशों में कम हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि

केवल इसकी वजह से हुआ है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक साधनों का सवाल है, 2004-2005 में 1675 करोड़ इस योजना के लिए पहली दफा दिया गया था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में 1232 करोड़ और दिए गए। लेकिन मैं यह इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की योजना का जो स्तर है, यह पहली बार हुआ है। अलग-अलग राज्यों में योजनाएं थीं, किंतु वे प्रदेश के अपने व्यय से ही किया करते थे। मैं मानता हूं कि तमिलनाडु में एक बहुत अच्छी परंपरा डाली गई है, कामराज जी ने उसकी शुरुआत की और पीछे के शासनों ने उसे बनाकर रखा, उसकी उन्नति की, जिसकी वजह से आज सबसे अच्छा तमिलनाडु का उदाहरण इस योजना को कार्यान्वित करने में है। इसी प्रकार से हमें और प्रदेश में भी कोशिश करनी है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, मेरे ऊपर उसका एक ही असर हुआ कि इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में, हमारे संसद के माननीय सदस्य इनकी कमियों की वजह से चिंतित हैं और इच्छुक हैं कि उन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। यही सबसे बड़ा कारण है कि मिड डे मील योजना सफल हो। यह बात कहते हुए मैं बहुत उत्साहित हूं कि करीब-करीब सभी प्रदेशों ने अपनी शैक्षणिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग मिड डे मील का बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, इस स्कीम को व्यापक और सही तरीके अमल में लाने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए हम सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, वहां के सम्मानित मुख्य मंत्रियों के सहयोग से उठाएंगे। मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जहां भी शिकयतें आएंगी, जिनका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। जैसी सभी की अपेक्षा है कि इस स्कीम का उस स्तर पर लाया जाए, वैसी ही हमारी भी चेष्टा है।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: उपसभापति जी, एक बड़े ही अहम सवाल का जवाब आना बाकी है...(व्यवधान)... उपसभापति जी, यह बड़ा अन्याय होगा...**(व्यवधान)**... एक बड़े सवाल का जवाब आना बाकी है कि दलित महिलाओं का हाथों के बनाए खाने को...**(व्यवधान)**...

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی : اُسچاپتی جی، ایک بڑے ہی اہم سوال کا جواب آنا باقی ہے .....مداخلت.....اُپ سچاپتی جی، یہ بڑا انیائے ہوگا .....مداخلت.....ایک بڑے سوال کا جواب آنا باقی ہے کہ دلت مہیلاؤں کے ہاتھوں کے بنائے رکھنے کو.....مداخلت .. [ ]

श्री उपसभापति: जवाब दिया है....**(व्यवधान)**

†Translitration in Urdu Script.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: They are giving Rs 1.25 per student टू रुपीज दे रहे हैं, दिल्ली में एन.डी.एम.सी. स्टूडेंट को और रूरल में 1.25 दे रहे हैं, It is not sufficient. I want to request the Minister to increase the amount per student, then only the scheme will work अदरवाइज उसे खा जाएंगे, यह मेरा कहना है।

श्री अर्जुन सिंह: उपसभापति जी, जहां तक साधनों का सवाल है, तो साधनों की सीमा तो रहेगी। अगर हर प्रदेश की सरकार इस मामले में केवल केन्द्र सरकार पर निर्भर करेगी, तो वह शायद न्यायोचित नहीं होगा।

STATEMENTS BY MINISTERS

MR DEPUTY CHAIRMAN: Statements by Ministers Shri P R Kyndiah and Kumari Selja.

Status of Implementation of Recommendations Contained in the Second Report of Standing Committee on Social Justice and Empowerment Pertaining to Ministry of Tribal Affairs

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH-EASTERN REGION (SHRI P.R KYNDIA). Sir, I beg to lay a copy of the statement on theTable of the House.

Status of Implementation of Recommendations Contained in the First and Fourth Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Urban Development

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (KUMARI SELJA): Sir, I lay a copy of the statement on the Table of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11. A.M.

The House then adjourned at fifty-nine minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 10th May 2005.

MGIPMRND—1411RS(S4)—18-10-2005.